



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 2009/श्रावण 31, 1931

No. 151]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 2009/SRAVANA 31, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अगस्त, 2009

सं. टीएमपी/37/2005-आईएसएचपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/37/2005-आईएसएचपीएल

इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड

...आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 25 जनवरी, 2007 के अपने आदेश द्वारा अधिसूचना सं. 46 दिनांक 22 फरवरी, 2007 के माध्यम से इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के 31 मार्च, 2009 तक की वैध अवधि वाले दरमान को अधिसूचित किया था।

2. 27 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा, प्रचलित दरमान की वैधता 31 जुलाई, 2009 तक बढ़ाते हुए आईएसएचपीएल को सलाह दी गई कि वह, दरमान के सामान्य संशोधन के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक पूर्ण प्रस्ताव दाखिल करे।

3. दिनांक 25 जून, 2009 के अपने पत्र के द्वारा आईएसएचपीएल ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। आईएसएचपीएल के प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के संगठनों से विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। आईएसएचपीएल के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इसे अंतिम विचार-विमर्श के लिए मामला को परिपक्व होने के लिए और समय लगेगा।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर, 2009 तक अथवा इस के प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए आईएसएचपीएल के प्रस्ताव पर पारित होने वाली आदेश की कार्यान्वयन प्रभावी तिथि तक या जो भी पहले हों विस्तार प्रदान करता है।

5. जैसाकि 27 मार्च, 2009 के आदेश में दिया गया है, निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल, 2009 से बाद की अवधि के लिए ग्राह्यलागत तथा अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक, यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष सामने आता है तो ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित कर लिया जाएगा।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन / III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th August, 2009

No. TAMP/37/2005-ISHPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the International Seaports (Haldia) Private Limited, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/37/2005-ISHPL

International Seaports (Haldia) Private Limited

...Applicant

ORDER

(Passed on this 28th day of July, 2009)

This Authority *vide* its Order dated 25th January, 2007 had notified the Scale of Rates of International Seaports (Haldia) Private Limited (ISHPL) with a validity period till 31st March, 2009 *vide* Notification No. 46 dated 22nd February, 2007.

2. The validity of the existing Scale of Rates was extended till 31st July, 2009 *vide* Order dated 27 March, 2009 with an advice to the ISHPL to file a complete proposal for general revision of its Scale of Rates in the formats prescribed by this Authority.

3. The ISHPL *vide* its letter dated 25th June, 2009 has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates. The ISHPL proposal has been taken on consultation with the relevant users/user organizations. The consultation process on the proposal of ISHPL is on and it will take time for the case to mature for final consideration.

4. This Authority, therefore, extends the validity of the existing Scale of Rates of ISHPL till 31st October, 2009 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of ISHPL for general review of its tariff, whichever is earlier.

5. As already stipulated in the Order dated 27th March, 2009, if any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2009, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/ 143/09-Exty.]